

सीमाओं से परे, सात्वना और आश्रय के लिए ब्लूप्रिंट

द हिन्दू

पेपर- II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध)

आज, दुनिया में 43.4 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी हैं, और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों के कारण, यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जैसे-जैसे यह संख्या बढ़ रही है, हम इन लोगों को जरूरतों, आशंकाओं, उम्मीदों और चाहतों वाले इंसान न मानकर, सांख्यिकीय संकलन के आंकड़ों के रूप में देखने का जोखिम भी उठा रहे हैं। फिर भी, वास्तव में, वे यही हैं। और विश्व शरणार्थी दिवस (20 जून) उन सभी इंसानों के बारे में सोचने का एक गंभीर अवसर है – सपनों और इच्छाओं, हँसी और खुशी वाले परिवारों की एक निरंतर श्रृंखला – जिनके जीवन उजड़ गए हैं, वे सभी घर जो नष्ट हो गए हैं, और वे सभी भविष्य जो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन यह सुरक्षित आश्रयों, सुनिश्चित शरण, शरणार्थियों की सुरक्षा और पाए गए समाधानों के बारे में सोचने का भी अवसर है।

भारत इस मार्मिक दिन को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार, इतिहास हमारे पक्ष में है। शरण देने का हमारा रिकॉर्ड हजारों साल पुराना है, ईसा से सदियों पहले बेबीलोनियों और फिर रोमनों द्वारा उनके जेरूसलम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भारत भाग आए यहूदियों से लेकर फारस में इस्लामी उत्पीड़न से बचने वाले जोरास्ट्रियन तक, पूर्वी बंगालियों तक – जिनके राष्ट्रवाद के लिए हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिससे बांग्लादेश बना – हाल के वर्षों में तिब्बती और श्रीलंकाई तमिल, नेपाली, अफगान और रोहिंग्याओं की धाराएँ। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसने इतिहास के सबसे भयावह शरणार्थी संकटों में से एक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्त की, जब 13 मिलियन से 15 मिलियन लोग भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बनाई गई सीमाओं को पार कर गए, हम सभी शरणार्थियों के सामने आने वाले खतरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने में मदद करने की जरूरत है।

उपयुक्त कानून बनाने की मांग

दुनिया भर से आए शरणार्थियों को सात्वना और आश्रय देने के हमारे गौरवशाली इतिहास के बावजूद, यह विडंबना है कि भारत न तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन (जो मेजबान देशों के दायित्वों के साथ-साथ शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के अधिकारों को रेखांकित करता है) और न ही इसके 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता है। न ही हमारे देश में घरेलू शरण ढांचा है। जबकि, हमारे इतिहास के साथ, हमें शरणार्थी अधिकारों के सवाल पर वैश्विक मार्च का नेतृत्व करना चाहिए, हमारे वर्तमान कार्य और कानूनी ढांचे की कमी हमारी विरासत को कोई श्रेय नहीं देती है, हमें दुनिया की नजरों में शर्मिंदा करती है, और हमारे शानदार पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है।

इन बड़ी कमियों को दूर करने के लिए ही मैंने फरवरी 2022 में लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें शरणार्थी और शरण कानून बनाने की मांग की गई थी। मेरे विधेयक में शरण चाहने वालों और शरणार्थियों को पहचानने के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए थे, और इस तरह की स्थिति से मिलने वाले विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। यह कानून इसलिए प्रस्तावित किया गया क्योंकि हमारी सरकार गैर-वापसी के अंतरराष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत का सम्मान करने में विफल रही – शरणार्थी कानून की आधारशिला, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश को किसी व्यक्ति को ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए जहाँ उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है – और इससे भी अधिक, यह अजनबियों को शरण देने की भारत की बेदाग परंपरा के साथ विश्वासघात है।

शरण विधेयक, 2021 शीर्षक से यह विधेयक हमारी सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के दो जत्थों को म्यांमार में निष्कासित करने के तुरंत बाद लाया गया, जबकि वे जिस देश से भागे थे, वहां उन्हें उत्पीड़न का गंभीर खतरा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए प्वापसी के इस कार्य को करने में, हमारी सरकार ने धार्मिक कट्टरता (शरणार्थी मुस्लिम थे) और असहिष्णुता दोनों को उजागर किया। दरअसल, 2017 में, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक परिपत्र जारी किया, जिसके कारण उन्हें भारत भर के हिरासत केंद्रों में बेरहमी से फेंक दिया गया, जहां वे दयनीय परिस्थितियों में सड़ते रहे - अपने परिवारों के साथ संवाद करने में असमर्थ और चिकित्सा सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता और पानी की आपूर्ति तक पहुंच के बिना - जब तक उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता। अगस्त 2023 तक, पूरे भारत में 700 से अधिक रोहिंग्या हिरासत में थे।

सरकार अरुणाचल प्रदेश में चकमा और मिजोरम में म्यांमार के लोगों के प्रति भी अमानवीय रही है। मेरे विधेयक में अधिकारियों द्वारा इस तरह के मनमाने आचरण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसने सभी विदेशियों को - चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म कुछ भी हो - भारत में शरण लेने का अधिकार दिया। इसने ऐसे सभी आवेदनों की समीक्षा और निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय शरण आयोग के गठन का भी आह्वान किया। बिना किसी अपवाद के, गैर-वापसी के सिद्धांत की दृढ़ता से पुष्टि करते हुए, मैंने बहिष्कार, निष्कासन और शरणार्थी की स्थिति के निरसन के कारणों को निर्दिष्ट किया, इस प्रकार सरकार के संप्रभु अधिकार का सम्मान करते हुए उसके विवेक को सीमित किया।

शरण विधेयक, 2021 शीर्षक से यह विधेयक हमारी सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के दो जत्थों को म्यांमार में निष्कासित करने के तुरंत बाद लाया गया, जबकि वे जिस देश से भागे थे, वहां उन्हें उत्पीड़न का गंभीर खतरा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए प्वापसी के इस कार्य को करने में, हमारी सरकार ने धार्मिक कट्टरता (शरणार्थी मुस्लिम थे) और असहिष्णुता दोनों को उजागर किया। दरअसल, 2017 में, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत करते हुए एक परिपत्र जारी किया, जिसके कारण उन्हें भारत भर के हिरासत केंद्रों में बेरहमी से फेंक दिया गया, जहां वे दयनीय परिस्थितियों में सड़ते रहे - अपने परिवारों के साथ संवाद करने में असमर्थ और चिकित्सा सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता और पानी की आपूर्ति तक पहुंच के बिना - जब तक उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता। अगस्त 2023 तक, पूरे भारत में 700 से अधिक रोहिंग्या हिरासत में थे।

सरकार अरुणाचल प्रदेश में चकमा और मिजोरम में म्यांमार के लोगों के प्रति भी अमानवीय रही है। मेरे विधेयक में अधिकारियों द्वारा इस तरह के मनमाने आचरण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसने सभी विदेशियों को - चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म कुछ भी हो - भारत में शरण लेने का अधिकार दिया। इसने ऐसे सभी आवेदनों की समीक्षा और निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय शरण आयोग के गठन का भी आह्वान किया। बिना किसी अपवाद के, गैर-वापसी के सिद्धांत की दृढ़ता से पुष्टि करते हुए, मैंने बहिष्कार, निष्कासन और शरणार्थी की स्थिति के निरसन के कारणों को निर्दिष्ट किया, इस प्रकार सरकार के संप्रभु अधिकार का सम्मान करते हुए उसके विवेक को सीमित किया।

सस्पेंस की स्थिति में:

शरणार्थियों से निपटने के लिए एक सुसंगत और व्यापक कानून की अनुपस्थिति में, हमारे पास शरणार्थी प्रबंधन पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव है। हमारे पास विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट अधिनियम (1967), प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, नागरिकता अधिनियम, 1955 (इसके भयावह 2019 संशोधन सहित) और विदेशी आदेश, 1948 जैसे कई कानून हैं, जिनमें सभी विदेशी व्यक्तियों को विदेशी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि भारत ने न तो इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सदस्यता ली है और न ही शरणार्थियों से निपटने के लिए कोई घरेलू विधायी ढाँचा स्थापित किया है, इसलिए उनकी समस्याओं से तदर्थ तरीके से निपटा जाता है और अन्य विदेशियों की तरह, उन्हें हमेशा निर्वासित किए जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है। शरणार्थियों की सुरक्षा की बात करते समय, हमें खुद को केवल शरण प्रदान करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर तंत्र की आवश्यकता है कि शरणार्थी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकें - जिनमें से मुख्य चिकित्सा सुविधाएँ और शैक्षणिक संस्थान हैं - और अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए कानूनी रूप से नौकरी की तलाश कर सकें।

हम बेहतर कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। भारत को एक राष्ट्रीय शरण कानून बनाना चाहिए, जैसा कि मैंने संसद में पेश किया है। हम वर्तमान में दो लाख से अधिक शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या और अन्य असुविधाजनक शरणार्थियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार का अशिष्ट रवैया हमें वैश्विक स्तर पर बदनाम करने का जोखिम उठाता है। अगर यह कानून बन जाता, तो मेरा विधेयक भारत को दुनिया में शरण प्रबंधन के मामले में सबसे आगे रखता। यह शरणार्थियों से निपटने के दौरान मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी दृढ़ और चिरकालिक प्रतिबद्धता को सही साबित करता।

न्यायपालिका की बागडोर संभालना

1996 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न केवल भारतीय बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अलंघनीय अधिकार प्राप्त हैं। इन आधारों पर, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य के ऐतिहासिक मामले में, 1995 में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले चकमा शरणार्थियों को जबरन बेदखल करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि शरण के लिए आवेदन पर उचित तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, और जब तक शरण देने या न देने पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राज्य किसी शरणार्थी को जबरन बेदखल नहीं कर सकता। इसलिए, हमारी न्यायपालिका ने हमें पहले ही सुनहरे रास्ते की ओर इशारा कर दिया है: अब हमें इस पर ईमानदारी से चलना चाहिए। फिर भी, कई बार, विभिन्न न्यायाधीशों ने मौलिक रूप से अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जैसा कि हमने रोहिंग्या मामले में खूब देखा। शरणार्थियों के अधिकारों के अधिनियमन और गणना से न्यायाधीश-केंद्रित दृष्टिकोणों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी - या इससे भी बदतर, गृह मंत्रालय के नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की सनक पर निर्भरता कम हो जाएगी।

दुनिया भर में शरणार्थियों की समस्याएँ ऐसी समस्याएँ हैं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व समुदाय के एक स्तंभ और उभरते बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण ध्रुव के रूप में भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए - अपनी धरती पर और साथ ही वैश्विक मंच पर - इस महान कार्य में, शरणार्थियों के लिए समाधान तैयार करना जो सीमाओं से परे ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। ऐसा करके, हम अपनी खुद की बेहतरीन परंपराओं और अपने लोकतंत्र के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे, साथ ही यह प्रदर्शित करेंगे कि हम वास्तव में वही हैं जो हमने हमेशा दावा किया है: एक विश्वगुरु, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, 'मानवता के और भी बड़े उद्देश्य की सेवा करने के लिए अथक प्रयास करना। यह हम सभी के लिए एक सार्थक आकांक्षा है जो इस बात की परवाह करते हैं कि भारत घर और दुनिया दोनों में किस चीज के लिए खड़ा है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: भारत और शरणार्थियों से जुड़े नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है।
2. 2017 में, गृह मंत्रालय ने रोहिंग्याओं को 'अवैध प्रवासियों' के रूप में नोटिफाई किया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of India and regulation related to refugees:

1. India is a signatory to the United Nations Refugee Convention.
2. In 2017, the Home Ministry had notified the Rohingyas as "illegal immigrants".

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : B

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: 'भारत का शरणार्थियों को लेकर विस्तृत इतिहास होने के बाद भी भारत किसी मजबूत वैश्विक और घरेलू कानून से नहीं जुड़ा है।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत का शरणार्थियों को लेकर विस्तृत इतिहास की चर्चा कीजिए।
- दूसरे भाग में वैश्विक स्तर पर और भारत में मौजूद शरणार्थी कानून की चर्चा कीजिए साथ ही भारत के स्तर पर मौजूद कमियों की चर्चा कीजिए।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।